not wish to disclose details, but sufficient steps have been taken to ensure that no fraudulent nomination order can be served upon any indenting department any more.

MR. CHAIRMAN : Mr. Radhakrishna. Half a minute.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA : Sir, I was a Member of the Andhra Pradesh Public Service Commission before I became an MP here. I know that the Andhra Pradesh Public Service Commission is using computers for evaluation of answer-papers and for tabulation also. It is quite foolproof and there is no scope for corruption and irregular appointments. I would like to know whether the Government is going to use computers for this purpose in the Staff Selection Commission also.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, we are using computers for tabulating results. The racketeering was not in evaluation or in compilation, but in the nomination orders. Those were fictitious orders.

MR. CHAIRMAN : Next Question, Mr. Kapil Verma.

SHRI KAPIL VERMA : Sir, I put my question. Question No. 247.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे

*242. **श्री रामसिंह भाईपातलीयाभाई राठवा** : क्या गृह मंत्री 6 नवम्बर, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 356 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारणों की जांच करायी है ;

(ख) इन दंगों में कुल कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है, और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) दंगा पीड़ित व्यक्तियों को अब तक क्या मुआवजा तथा अन्य सुविधाएं दी गयी हैं ।

गृह मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) साम्प्रदायिक घटनाएं, साम्प्रदायिक और समाज विरोधी तत्वों का काम है, जो छोटे छोटे विवादों और झगड़ों को साम्प्रदायिकता का रंग देते हैं और खासतौर पर धार्मिक जलूसों और सभाओं के मौकों पर सक्रिय हो जाते हैं ।

साम्प्रदायिक दंगों/घटनाओं के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में, केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से, इस प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना/न्यायालय निर्धारित करने का, अनुरोध करती रही है ।

जहां तक इन दंगों में सम्पत्ति की हुई क्षति का संबंध है, 1 जनवरी, 1986 से 31 अक्तूबर, 1986 के दौरान देश में हुए बड़े साम्प्रदायिक दंगों और सम्पत्ति को हुए नुकसान के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(घ) साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और अनुग्रहपूर्वक अनुदान की अदायगी करने के बारे में केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1983 में विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भेजे थे । इन दिशा निर्देशों को विभिन्न राज्य सरकारों ने अधिकांशतः स्वीकार कर लिया है ।

विवरण

स्थान और तिथि	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति की क्षति (रु० लाख में)	साम्प्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि (रु० लाखों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार			
नवादा	*10	उपलब्ध नहीं है	0.87
अप्रैल, 22	(*बिहार सरकार के अनुसार केवल 3 मौतें साम्प्रदायिक हिंसा के कारण हुई कही जा सकती है।)		
गुजरात			
अहमदाबाद	9	7.73	2.64
जनवरी, 5–7	5	0.38	उ.न.
जनवरी, 22–24	4	0.05	उ.न.
मार्च, 26–30			
जुलाई, 9–17	49	63.16	4.85 इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों के लिये 6 राहत शिविर स्थापित किये।
बेरावल			
मार्च, 26–27	13	246.98	3.72
नादियाड			
अगस्त, 9–16	7	1.01	उ.न.
बड़ौदा			
सितम्बर, 17–20	5	3.79	उ.न.
कर्नाटक			
रामनगरम्			
जुलाई, 22–25	5	उपलब्ध नहीं है	उ.न.

(1)	(2)	(3)	(4)
मध्य प्रदेश			
सिहोर फ़रवरी, 16–17	8	100.00	2.33 इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने दंगा पीड़ित व्यक्तियों के लिये एक राहत शिविर स्थापित किया
महाराष्ट्र			
नासिक मई, 10	8	43.05	3.72
पनवल मई, 10	2	66.48	उ.न.
उत्तर प्रदेश			
मेरठ फ़रवरी, 26	2	7.42	1.00
नियोरिया (पीली भीत) मार्च, 26–27	26	—	5.47
इलाहाबाद			
जून, 14–18	9	2.65	उ.न.

देश में टेलीविजन उद्योग

245. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीविजन उद्योग की क्या स्थिति है और यह देश की ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टेलीविजन सैटों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कहां तक सक्षम है ;

(ख) सरकार ने ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टेलीविजन आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की है ; और

(ग) भारतीय ट्रांजिस्टर रेडियो उद्योग को जापान तथा विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सक्षम बनाने हेतु सरकार की नीति और कार्यक्रम क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाण उर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० के नारायण) :

(क) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सैटों को विनिर्माण मख्यत: स्वदेशी संघटक पूर्जों पर ही आधारित है जहां तक